संख्या-71/2023/281/001-23-10-22-03(सेतु)22 टी0सी0

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के 01 लघु सेतु एवं जनपद बदायूँ के 01 लघु सेतु अर्थात कुल 02 लघु सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग), उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-184/नदी सेतु/बस्ती क्षेत्र/सेतु-3/2022 दिनांक 13.02.2023 एवं पत्र संख्या-50/प्रा0आगणन-बदायूँ/टिटौली से वागरपुर/सेतु-6/22-23 दिनांक 09.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-सिद्धार्थनगर के 01 लघु सेतु एवं जनपद बदायूँ के 01 लघु सेतु अर्थात कुल 02 लघु सेतुओं के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 1132.26 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0 57/83 से कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 566.14 लाख (रूपये पॉच करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्रम सं0	जनपद	योजना का नाम		वित्तीय वर्ष 2022-2023 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिद्धार्थनगर	जनपद-सिद्धार्थनगर में महुआ से पजोहा सम्पर्क मार्ग पर परासी नाले पर 4x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 बॉक्स पुलिया, पहुंच मार्ग, कनेक्टिंग रोड एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	438.15	172.61	46.47	219.08	लो0नि0वि0
2	बदायूँ	जनपद बदायूँ में टिटौली से वागरपुर मार्ग पर स्थित अरिल नदी पर मुख्य सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण	694.11	273.45	73.61	347.06	लो0नि0वि0
		योग -	**1132.26**	**446.06**	**120.08**	**566.14**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(17) परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों व मानकों के अंतर्गत है।

(18) प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी उसका पूर्णतः लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिष्चित किया जायेगा।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(20) परियोजना में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति सुनिश्चित की जायेगी।

(21) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिष्चित की जायेगी।

(22) प्रस्तावित परियोजना के संबंध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित सेतु के दोनो तरफ के पहुंच मार्ग/अतिरिक्त पहुंच मार्ग स्वीकृत है।

(23) परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग संबंधी लागत का आंकलन कर लिया गया है। भविष्य में उक्त दोनों मदों में वृद्धि न हो यह सुनिष्चित किया जायेगा।

(24) परियोजना को भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य पूर्ण करने सहित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से कुल 09 माह में पूर्ण करना व तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिष्चित किया जायेगा।

(25) परियोजना के संबंध में मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा।

(26) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दि0 07 जून, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दि0 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 4,46,06,000 (रुपये चार करोड छियालिस लाख छः हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,20,08,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-630-X-2022-23-दिनांक: 03-03-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-71/2023/281(1)/23-10-22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- संबंधित कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।